THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) and (b). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Survey of Bay of Bengal by Union Carbide

3419. SHRI C. JANARDHANAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the position of the Union Carbide India in the fishing industry of the country;

(b) whether this company has a programme to survey the Bay of Bengal; and

(c) if so, the purpose of it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) Union Carbide India Ltd. are owing and operating 2 trawlers which were imported in 1970. There are 91 off-shore and deep sea fishing vessels and over 9,000 coastal mechanised vessels in operation in the country. The firm has exported 206.68 tonnes of marine products valued at Rs. 72.67 lakhs in 1973 against the total exports of 48.306 tonnes valued at Rs. 79.25 crores during the year.

The firm applied for the import of 4 more vessels under the scheme for the import of 30 vessels launched in 1968. However, subsequently the firm withdraw the application. The firm also applied for the import of 8 vessels under the scheme for the import of 50 vessels notified by the Government in June, 1973. This application has also been subsequently withdrawn by the firm.

(b) and (c). Surveys of marine fisheries resources in the in-shore waters are being conducted by the State Governments, while the surevys of the off-shore and deep sea areas are done by the Government of India. No proposal has been received from M|s Union Carbide India Ltd. by the Government proposing survey of the Bay of Bengal for fishing.

भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार देने के लिए किये गये उपाय

3420. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिहीन श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष क्या पग उठाये गये हैं; और

(ख) इस प्रकार से इन वर्षों में लाभान्वित होने वाले श्रमिकों की राज्य-वार संख्या क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख). ग्राम रोज़गार की त्वरित योजना को तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित करने का काम अप्रैल, 1971 से आरम्भ किया गया था। इस योजना में देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 1000 व्यक्तियों को रोज़गार देने की परिकल्पना की गई थी। मजदूरों को विभिन्न अवधियों के लिए काम पर लगाया जाता है। इसलिये सूचना रोज़गार के श्रम दिनों के रूप में इकट्ठी की जाती है, न कि लाभ पाने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में। यह मान लेने पर कि व्यक्तियों को औसतन वर्ष भर में 150 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है, तो वर्ष 1971-72 में लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति जिला लगभग 1,500 होगी और वर्ष 1972-73 में प्रति जिला लगभग 2,500 होगी। चालू वर्ष में प्रति जिला 1,800 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने की उम्मीद है। एक विवरण जिस में लाभ उठाने वाले मजदूरों की संख्या (राज्यवार) दी गई